सशक्त युवाओं के दस वर्ष

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Research Team

Abhay Singh
Research Associate
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Manujam Pandey
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Design

Ajit Kumar Singh
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

विषय सूची

1	भूमिका	4
2	युवा शक्ति के बदलाव की यात्रा के दस वर्ष	5
3	अगली पीढ़ी के लिए प्लान बनाने वाले स्टेट्समैन हैं पीएम मोदी **- अमिताभ सिन्हा**	11
4	सशक्त हो रही भारत की युवा पीढ़ी **- प्रो. बाला लखेंद्र**	13

भूमिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि दुनिया ने मान लिया है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं – जनसांख्यिकी और लोकतंत्र.

वर्तमान में भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार अपनी इस क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है.

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 30 वर्ष बाद मौजूदा शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करने की शुरुआत कर दी है. एनईपी भारतीय स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श बदलाव की प्रक्रिया परिलक्षित होती है. यह श्रेष्ठ ज्ञान पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति बनाना है.

पिछले दस वर्षों में देशभर में रिकार्ड संख्या में आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले हैं. मोदी सरकार का शिक्षा के साथ साथ कौशल और कौशल विकास पर भी जोर रहा है.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जिससे उनके रोजगार की संभावनाओं में व्यापक परिवर्तन आया.

युवाओं के लिए नए औपचारिक रोजगार सृजित करने की मोदी सरकार की प्राथमिकता की सफलता को नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में भारी वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है. भारत को निवेश के एक आकर्षक केंद्र में बदलने की दिशा में लगातार प्रयास, एमएसएमई को सहायता और घरेलू उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आदि कार्यक्रमों ने युवा भारतीयों के लिए अवसर का निर्माण करने में योगदान दिया है.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 10 लाख नौकरियों के लिए एक भर्ती अभियान रोजगार मेले की शुरुआत की है. सरकार का जोर सिर्फ रोजगार सृजित करने पर ही नहीं बल्कि उद्यमिता का विकास युवाओं को रोजगार खोजने वाले से रोजगार देने वाला बनाने पर भी है. पहले जहाँ लोग जोखिम लेने से बचते थे और वेतनभोगी नौकरियों का विकल्प चुनते थे. इसके विपरीत आज युवा अनुकूल नीतिगत माहौल के कारण आगे बढ़ने को उत्सुक है.

निःसंदेह पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी लक्ष्यों और प्रयासों में युवाओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है.

डॉ अनिर्बान गांगुली

चेयरमैन - डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन,

नई दिल्ली

“

आज देश का मिजाज भी युवा है, और देश का अंदाज़ भी युवा है।

और जो युवा होता है, वो पीछे नहीं चलता, लीड करता है।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नासिक में पीएम मोदी, 12 जनवरी 2024

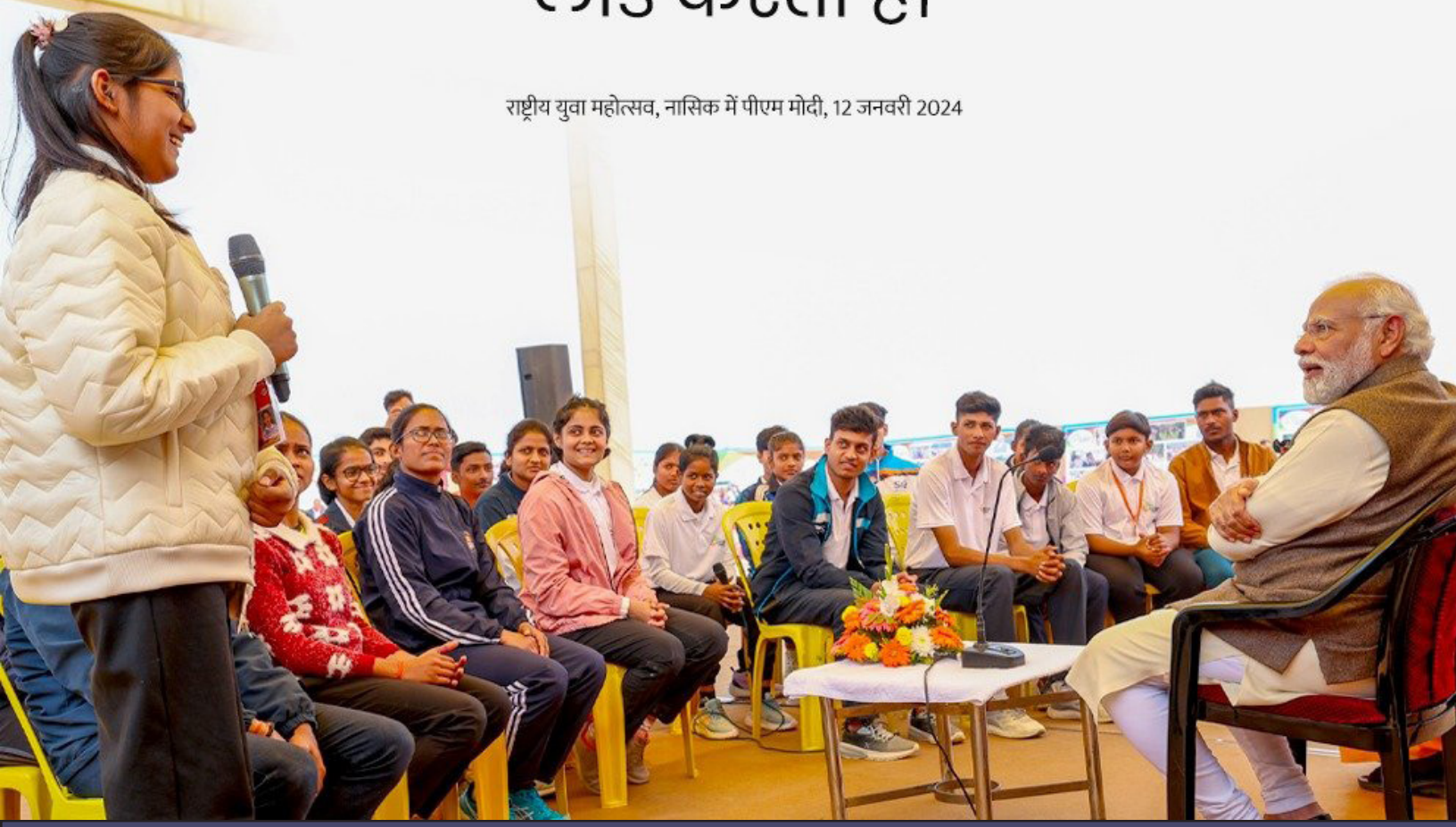

युवा शक्ति के बदलाव की यात्रा के दस वर्ष

शिक्षा

भारत के युवाओं के लिए उज्जवल और सशक्त भविष्य के निर्माण को लेकर मोदी सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास पर केन्द्रित महत्वकांक्षी पहल की एक श्रृंखला शुरू की है. इन प्रयासों के केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन है जो एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है. इसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर संरचनात्मक सुधार लाना है.

पीएम श्री (स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया)

जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने 14 हजार 500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों के स्थापना की शुरुआत की है. इनमें से 6 हजार से अधिक स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है. इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने और अपने क्षेत्रों में मॉडल स्कूल बनाने के लिए गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा.

उच्च शिक्षा संस्थानों में वृद्धि

पिछले दशक में उछ शिक्षा संस्थानों का उल्लेखनीय विस्तार देखा गया है. इसके तहत 7 आईआईटी, 8 आईआईएम और 385 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई. शैक्षिक बुनियादी ढांचे में यह उन्नति 21वीं सदी में भारत की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करने की दिशा में अहम पहल है.

इसी तरह का ही विस्तार चिकित्सा शिक्षा में भी देखा जा सकता है. युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पिछले दशक में 16 एम्स और 319 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई.

इससे पहले 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से कम ही मेडिकल कॉलेज थे. पिछले एक दशक में एमबीबीएस सीटों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है. इसके अलावा युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर के अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम हो रहा है.

लैंगिक समावेशिता और सामाजिक सशक्तिकरण

उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2014 में 3.4 करोड़ छात्रों से बढ़कर 2023 में 4.1 करोड़ हो गया है. उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. सकल नामांकन अनुपात वित्त वर्ष 2010 में 12.7 प्रतिशत था जो 2020 में बढ़कर 27.9 प्रतिशत हो गया है. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए नीतिगत निर्णयों से देशभर में ड्रॉपआउट की दर कम हुई है. इस तरह की पहल से विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले समाज को लाभ हुआ है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के नामांकन दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

महत्वपूर्ण प्रगति

समग्र शिक्षा पहल ने 2018-19 से 2023-24 तक स्कूलों को अपग्रेड करने, नए आवसीय स्कूल खोलने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

- 3062 स्कूलों को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड किया गया.
- 235 नए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास खोले गए.
- अतिरिक्त कक्षाओं सहित 97364 स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया.
- आईसीटी और डिजिटल पहल के तहत 1.2 लाख स्कूलों को शामिल किया गया.
- 8619 स्कूल व्यावसायिक शिक्षा के तहत कवर किए गए हैं.
- 28447 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अलग शौचालयों का निर्माण किया गया.

शिक्षा में डिजिटल लर्निंग और नवाचार पर बल

स्वयं प्रभा और एमओओसी जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षण का विस्तार किया जा रहा है. इसके तहत 200 चैनलों के साथ 31 भाषाओँ में प्रसारण के लिए 13 हजार से अधिक कंटेंट मोड्यूल तैयार किए गए हैं. इस तरह के प्रयास से अंतर को कम किया जा रहा है और शिक्षा तक सभी की पहुँच को आसान बनाया जा रहा है.

मातृभाषा और समावेशी भाषा पर जोर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू मातृभाषाओं और अन्य भारतीय भाषओं में शिक्षा पर जोर देना है. इंजीनियरिंग, चिकित्सा और क़ानून जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक यह समावेशी दृष्टिकोण फैला हुआ है.

युवाओं को सशक्त बनाने की मोदी सरकार की दृढ प्रतिबद्धता के कारण भारत का शिक्षण परिदृश्य मूलभूत बदलाव के दौर से गुजर रहा है. समावेशी भाषा, संस्थागत विकास, जेंडर सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति को शामिल करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने की राह पर ले जा रहा है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में हमारे युवाओं को सक्षम बनाता है.

कौशल भारत मिशन

कौशल भारत मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन है, जिसे जॉब मार्केट की मांगों को पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें नए कौशल से प्रशिक्षित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था. इस मिशन के माध्यम से 1.4 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है. इनमें से 24 लाख व्यक्तियों को नौकरी मिल चुकी है और 54 लाख व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने और उन्हें नए कौशल से प्रशिक्षित किया गया.

सितंबर 2023 में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत भारत की कौशल विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इसका लक्ष्य भारत में कौशल प्राप्त करने में आसानी है. इसके अतिरिक्त 3000 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ने देश के कौशल विकास बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया है.

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना

युवाओं में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य है. देश भर में 10 हजार अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई. यहाँ एक करोड़ से अधिक छात्र सक्रिय रूप से नवाचार आधारित गतिविधियों में लगे हुए हैं जो रचनात्मकता और समस्या समाधान के संस्कृति की नींव रख रहे हैं.

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के जरिए 2014 से 2022 के बीच आईटीआई में 1.1 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया. अप्रैल 2018 से मार्च 2023 के बीच 2 लाख लाभार्थियों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण दिया गया. यह योजना युवाओं में प्रतिभा को निखारने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सहायक है. 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और 3 विस्तार केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है. इनमें से 19 विशेष रूप से महिलाओं के लिए है.

शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अंतर को कम करना

व्यवहारिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचानते हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 28 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया. यह पहल सैधांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के बीच के अंतर को कम करती है. युवाओं को उनके चुने हुए क्षेत्रों में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती है. सितंबर 2023 में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करना है जिसमें कौशल उन्नयन और बिना गारंटी के रियायती ऋण तक शामिल है. योजना के तहत अब तक 1.39 करोड़ तक आवेदन आए, इनमें से 6.51 लाख पंजीकरण हो चुके हैं.

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

कौशल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता विश्व कौशल प्रतियोगिताओं में इसकी बढ़ती स्थिति से और अधिक रेखांकित होती है जो 2011 में 39वें स्थान से 2022 में 11वें स्थान पर पहुँच गई. यह तेजी विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं में क्षमता विकसित करने और कौशल को निखारने में मोदी सरकार के ठोस प्रयासों के चलते प्राप्त हुए परिणामों को दिखाता है.

इसका निष्कर्ष यह निकला कि भारत में कौशल विकास पहल युवा सशक्तिकरण और आर्थिक विकास की आधारशिला बनकर उभरी है. ठोस प्रयासों और नवीन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र अपने युवाओं को प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित कर रहा है. जैसे जैसे भारत कौशल विकास में निवेश जारी रखता है यह न केवल अपने युवाओं की क्षमता को दर्शाता है बल्कि देश को

समावेशी विकास और समृद्धि की ओर भी प्रेरित करता है.

रोजगार और उद्यमिता को सशक्त बनाना

सरकार ने रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है. हाल के वर्षों में सरकार की बहुआयामी रणनीतियों और अवसरों के साथ साथ आर्थिक नीतियों से युवा रोजगार और उद्यमिता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.

उद्यमिता सशक्तिकरण पर जोर

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इच्छुक उद्यमियों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है. इस योजना ने हमारे युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़ रूपए मूल्य के 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं. छोटे पैमाने के उद्योगों से लेकर नवोन्मेषी स्टार्ट अप तक पीएम मुद्रा योजना पूरे देश में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक रही है. इसके अलावा स्टार्ट अप इंडिया, फंड ऑफ़ फंड्स और स्टार्ट अप क्रेडिट गारंटी योजनाएं हमारे युवाओं की सहायता कर रही हैं. इससे हमारे युवा अब रोजगारदाता बन रहे हैं. सरकार के निरंतर प्रयासों से आज की तारीख में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 121013 हो गई है. इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 12.42 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया है.

युवा रोजगार में सकारात्मक रुझान

पिछले कुछ वर्षों में युवा आबादी के साथ साथ युवाओं में रोजगार का अवसर भी बढ़ रहा है. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी की दर जो 2017-18 में 17.8 प्रतिशत थी वह घटकर 2022-23 में 10 प्रतिशत हो गई है. इन छ वर्षों में नियोजित युवाओं का अनुपात 31 प्रतिशत से बढ़कर 40.1 प्रतिशत हो गया है. इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईपीएफओ में 1.38 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं. इनका जुड़ना भारत के युवाओं के लिए रोजगार के बढ़ते अवसरों को दर्शाता है जो देश के विजन के अनुरूप है. इसके अलावा रोजगार मेले के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया. इसमें 12 संस्करणों में 8 लाख से अधिक भर्ती पहले ही हो चुकी है. अटल इन्क्यूबेशन सेंटर ने भी 32 हजार से अधिक नौकरियां सृजित करने में योगदान दिया है.

खेलों में सशक्त होते युवा

हाल के वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियां, बुनियादी ढांचे का विकास और बढ़ती खेल अर्थव्यवस्था के कारण भारत के खेल परिदृश्य में बेहतर परिवर्तन देखने को मिला है. खेलों के प्रति देश के युवाओं के जूनून और समर्पण से प्रेरित यह नवजागरण भारत के दृष्टिकोण में आदर्श बदलाव को दिखाता है.

देश को अपने युवाओं पर गर्व है जो खेल स्पर्धाओं में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं. 2023 में एशियाई और एशियाई

पैरा खेलों में अब तक जीते गए सबसे अधिक पदक आत्मविश्वास के स्तर को दिखाते हैं. प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में ऐतिहासिक पदक जीतने से लेकर शतरंज जैसे व्यक्तिगत खेलों में असाधारण प्रतिभा दिखाने तक भारतीय एथलीटों ने लगातार बाधाओं को पार किया है. प्रगनानन्द जैसी युवा प्रतिभाओं का उद्भव और शतरंज ग्रैंडमास्टरों की संख्या में तेजी से वृद्धि सामरिक खेलों में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाती है.

सरकारी सहायता और नीतिगत पहल

भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का निर्माण, खेलो इंडिया अभियान के तहत देश में 300 से अधिक प्रतिष्ठित अकादमियों का निर्माण, 1000 खेलो इंडिया केंद्र और 30 से अधिक उत्कृष्टता केंद्र खेल संस्कृति को बदल रहे हैं. देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेलों को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, जिससे बचपन में ही खेल को करियर के रूप में चुनने के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी.

अगली पीढ़ी के लिए प्लान बनाने वाले स्टेट्समैन हैं पीएम मोदी

- अमिताभ सिन्हा

तीन दशक पहले कॉलेज में राजनीति शास्त्र तो सिर्फ सब्सिडियरी में पढ़ा था, लेकिन चंद लाईनें अब भी याद हैं. लिखा था कि जो अपने चुनावी घोषणापत्र में अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए वायदे करता है वो नेता होता है... लेकिन जो अपने घोषणा पत्र में अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लागू करता है उसे कहते हैं स्टेट्समैन. बीजेपी का संकल्प पत्र साबित करता है कि पीएम मोदी वाकई एक स्टेट्समैन ही हैं.

पीएम मोदी हमेशा से मुफ्त की रेवड़ी बांटने की खिलाफत करते रहे हैं. पीएम चाहते हैं कि नागरिकों का जीवन यापन सरकार के हस्तक्षेप पर निर्भर नहीं हो. इसलिए जब बीजेपी का शपथ पत्र जनता के सामने आया तो साफ हो गया कि मोदी सरकार विपक्षी गठबंधनो की तर्ज पर शार्ट टर्म प्लानिंग में नहीं चलना चाहती, बल्कि आने

वाली पीढ़ी को 2047 तक विकसित भारत का तोहफा देना चाहती है.

बीजेपी के संकल्प पत्र की शुरुआत में ही पीएम नरेंद्र मोदी का देश की जनता के नाम लिखा गया खुला खत भी है. इस खत की आखिरी दो लाईनें ही उनके ऐजेंडा का पूरा सार बयान कर देती हैं. पीएम ने लिखा है कि 'आपकी आशा-अकांक्षा को पूरा करना हमारा मिशन है. आपके सपने मेरी जिम्मेदारी हैं. आईए हम सब मिलकर ऐसा देश बनाएं जिस पर हमारी भावी पीढ़ी को गौरव हो.'

जनता के नाम लिखे इस खुले खत में पीएम ने अगले पांच सालों के लिए जनता का समर्थन तो मांगा ये कहते हुए मांगा कि 2014 का जन समर्थन पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकाल कर बड़े बदलाव किए. 2019 का बड़ा जनादेश विकास को बड़ी गति देने में सफल रहा. अब का जनादेश तमाम सुधारों को लागू कर 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढेगा. इसके लिए मोदी सरकार 24 घंटे काम करेगी और यही नरेंद्र मोदी की गारंटी है.

2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सीमम गवर्नेंस पर उनकी सरकार काम करेगी. अब सत्ता में 10 साल पूरे हो रहे हैं और पीएम मोदी ने आम जनता की सरकार पर निर्भरता कम करने की कोशिशें लगातार जारी रखी है... चाहे वो किसी भी वर्ग या संप्रदाय के हों. मोदी सरकार का पूरा ध्यान जनता के सशक्तिकरण के लिए है. न कि सिर्फ उनके लिए बनी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए . पीएम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश पूरी आबादी को सरकारी नौकरी नहीं देता है. मोदी सरकार की कोशिश ही रही है कि सबकी सरकार पर निर्भरता घटे. जिस लालफीताशाही के कारण लोग अपना काम नहीं कर पाते उसे दूर करना ताकि जनता को अपने स्वरोजगार में सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़े.

पीएम चाहते हैं युवा, महिला, कस्बों, गावों में लोग खुद रोजगार करें और दूसरों को रोजगार देने के काबिल बने. पीएम मोदी का संदेश यही है कि आम जनता के रोजमार्रा की जिंदगी और स्वरोजगार में सरकार का अभाव नही बल्कि उनका काम आसान करने में सरकार का प्रभाव झलके. यानि पीएम मोदी का ऐजेंडा यही है कि आम नागरिकों को जीवन के हर पल में सरकार का हस्तक्षेप नजर नहीं आए.

अब जब पूरी दुनिया कहने लगी है कि आने वाला समय भारत का समय है और एक बेहतर कल के लिए भारत की भूमिका भी स्वीकार कर रही है. ऐसे समय में भारत उडान भरने को तैयार है. तभी तो पीएम ने अपने संदेश में लिखा है कि अब हमें और परिश्रम करना है और हमने नई सरकार के लिए 100 दिनों की कार्ययोजना भी तैयार कर ली है.

अगले कार्यकाल में पीएम मोदी का लक्ष्य है देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना. साथ ही अगले जेनेरेशन रिफार्म्स पर देश को अमल में लाना. गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लडने का लक्ष्य भी पीएम मोदी ने रखा है. गरीबी हटाओ जैसे लोक लुभावन वायदों से दूर संकल्प पत्र पीएम मोदी के दिशा निर्देश पर खरा उतरा है. मोदी गारंटी तो है ही, लेकिन 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए वोट मांगना ये साबित करता है कि चिंता देश की भी है और देश का निर्माण करने वाली भविष्य की पीढ़ी की भी.

(लेखक न्यूज़ 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर है. प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं)

सशक्त हो रही भारत की युवा पीढ़ी

- प्रो. बाला लखेंद्र

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी औसत आयु 29 वर्ष है. लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है तो 50 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है. ऐसे में डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी के रूप में असीमित शक्तियों वाला राष्ट्र युवा सपनों को नई उड़ान दे रहा है. लगभग 4 वर्ष पूर्व 29 जुलाई को राष्ट्र के समक्ष आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए ज्ञान का ग्लोबल हब बनाने की पहल हो या मिशन के रूप में कौशल से युवाओं को लैस करना, स्टार्टअप से यूनिकॉर्न की पहल को संस्कृति बनाना या तकनीक डिजिटल से युवाओं को जोड़ना, सेना या अन्य जगहों पर युवाओं को नए अवसर प्रदान करना या खेलों को करियर से जोड़ सामाजिक सोच को बदलना, राष्ट्रीय युवा नीति के जरिए अमृतकाल की ओर बढ़ना हो या रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने की क्रांतिकारी पहल को मूर्त रूप देना, अमृत पीढ़ी के रूप में सदर्भित युवा शक्ति भारत की विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति बन गई है जो आने वाले 25 वर्षों में देश को नई उंचाई पर ले जाएगी और भारत को विकसित तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएगी.

भारत का जन भी युवा है और मन भी युवा है. भारत अपने सामर्थ्य, सपनों, चिंतन और चेतना से भी युवा है. इन्हीं विशेषताओं के कारण आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से देखती है. भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है. भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है. भारत वह है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है. वेदों में कहा गया है अपि यथा,
युवानो मत्सथा,

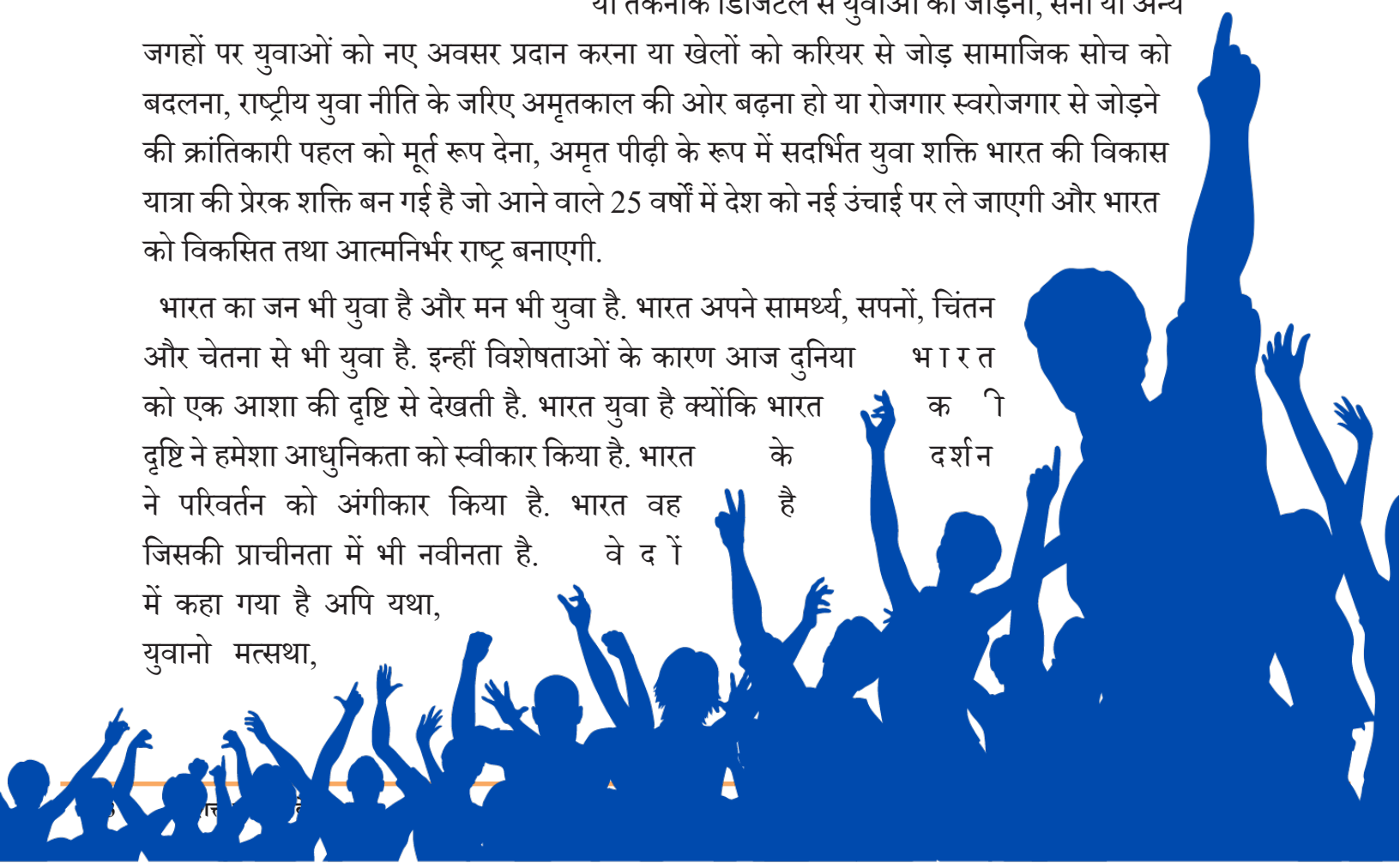

नो विश्वं जगत, अभिपित्वे मनीषा यानी ये युवा ही हैं जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं. युवा ही भारत के लिए राष्ट्र के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है तो इसके पीछे युवा हैं. आज हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है. भारत का लक्ष्य है इसे टॉप 3 में पहुंचाने का. देश की यह इकनोमिक ग्रोथ युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी. कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्रान्ति से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नए रास्ते खुलेंगे. आज के युवा इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं तो कल इसी ताकत से भविष्य का नेतृत्व करेंगे.

शिक्षा का ग्लोबल हब

एक देश पूरे विश्व में अपनी शिक्षा और शिक्षा नीतियों के कारण पहचाना जाता है. मोदी सरकार ने विश्व स्तरीय शिक्षा का सृजन किया है, जिससे देश का युवा सशक्त बन रहा है. प्रधानमंत्री मोदी बेहतर और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं. इसमें अब अंग्रेजी भाषा की बाध्यता नहीं है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी और उच्च शिक्षा के स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है. इंजीनियरिंग और आईटी जैसे तकनीकी विषय अब पांच क्षेत्रीय भाषाओं में भी किए जा सकते हैं. इससे न सिर्फ पंजीकरण बढेगा बल्कि वैश्विक सोच के साथ स्थानीय समस्याओं के समाधान की क्षमता भी छात्र छात्राओं में बढ़ेगी.

कौशल मिशन – कुशल भारत

युवाओं को उनकी शिक्षा, कौशल और अपेक्षाओं के अनुरूप रोजगार मिले, यह मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है. देश के अन्दर कितना रोजगार बढ़ रहा है, ये प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष सूचकांकों के जरिए पता चलता है. मजबूत आर्थिक नीतियों से लाखों रोजगार पैदा हो रहे हैं. प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत लोगों को कौशल से युक्त किया जा रहा है. सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं. अगर उदाहरण के तौर पर केवल ईपीएफओ के आंकडें देखें तो वर्ष 2018-19 के बाद साढ़े चार करोड़ से ज्यादा लोगों को औपचारिक नौकरी मिली है. देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़े हैं. यह मोदी सरकार में युवाओं का भरोसा दिखाता है.

खेल अब करियर की नई पहचान

पिछले 10 वर्षों में भारत में खेल का नया युग शुरू हुआ है. ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल महाशक्ति बनाने का भर का नहीं है बल्कि ये खेल के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है. एक समय था जब देश में खेलों को लेकर उदासीनता का ही भाव था. स्पोर्ट्स भी एक करियर हो सकता है यह कम लोग ही सोचते थे. इसकी वजह थी कि स्पोर्ट्स को सरकारों से जितना समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं था. इसलिए गरीब मध्यम वर्ग और गाँव देहात के बच्चों के लिए खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से लोगों की सोच में बदलाव आया है. इसमें खेलो इंडिया अभियान ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है. टोक्यो ओलम्पिक में अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन, पैरालंपिक के इतिहास में भारतीय टीम का श्रेष्ठ प्रदर्शन, टॉप्स कार्यक्रम आदि के माध्यम से जैसा समर्थन खेल और खिलाड़ियों को मिला वह अभूतपूर्व है.

निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार नीति, नीयत और नए अवसरों के आधार पर युवाओं को राष्ट्र की प्रगति का सारथी बना रही है, ताकि संकल्प से सिद्धि की यह यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे.

(लेखक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं)

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee

Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

Phone: 011-69047014

@spmrfoundation